

भारत: प्रगति और समृद्धि में भागीदार*

श्री संजय मल्होत्रा

इस ऐतिहासिक स्थल पर आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है मैं सीआईआई और यूएसआईएसपीएफ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने और अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। सीआईआई और यूएसआईएसपीएफ, दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार में साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूँ। आज अपने संबोधन में, मैं इस बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कैसे भारत आने वाले वर्षों में अवसरों, नवाचार और टिकाऊ विकास का एक गतिशील केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन और गतिशीलता का प्रदर्शन किया है। पिछले चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में, इसने 8.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था थी और अब भी बनी हुई है। इसने पिछले दशक (2010 से 2019) की 6.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से आगे काफी प्रगति की है।

इस वर्ष भी हमारी विकास दर 6.5 प्रतिशत पर मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और अस्थिरता में भारी वृद्धि के बावजूद यह संभव है। हालाँकि यह दर हाल के वर्षों की तुलना में और भारत की आकांक्षाओं से कम है, फिर भी यह मोटे तौर पर पिछले रुझानों के अनुरूप है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।

इसमें कोई आश्रय की बात नहीं है कि पिछले दस वर्षों में हम दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। क्रय शक्ति समता के मामले में हम पहले ही तीसरे स्थान पर हैं। नॉमिनल आधार पर भी हम

* भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) द्वारा आयोजित यूएस-इंडिया इकोनॉमिक फोरम में मुख्य भाषण, वाशिंगटन डीसी, 25 अप्रैल 2025।

जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हम 2047 तक, जब हम अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, 'विकसित भारत', यानी एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखते हैं। हालाँकि मध्यम से दीर्घावधि में भारत के विकास पथ में वृद्धि की गुंजाइश ज़रूर है, मैं हमारी निरंतर सफलता के प्रति आशान्वित हूँ। ऐसे कई सकारात्मक कारक हैं जो मुझे यह विश्वास दिलाते हैं। मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा।

नीति निरंतरता और स्थिरता

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश की दीर्घकालिक योजना के लिए निश्चितता के साथ राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता आवश्यक है। हमारा सक्रिय लोकतंत्र इसे सुनिश्चित करने में सक्षम रहा है, खासकर आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से, और सरकार में राजनीतिक दलों के बदलने के बावजूद भी। बाजार उन्मुख नीतियों पर केंद्रित आर्थिक उदारीकरण अब तक की सभी सरकारों में एक सुसंगत विषय रहा है। हो सकता है सुधारों की गति और विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रण समय-समय पर भिन्न रहा हो, फिर भी अधिक बाजार उन्मुख आर्थिक संरचना के प्रति प्रतिबद्धता नहीं बदली है। लगभग सभी क्षेत्रों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए चरणबद्ध तरीके से खोल दिया गया है। लगभग 90% एफडीआई अब स्वचालित मार्ग के तहत है। हाल के वर्षों में हमने अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलने के लिए उदारीकरण उपायों की एक शृंखला शुरू की है, विशेष रूप से रक्षा, बीमा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में।¹

वित्तीय स्थिरता

दूसरा, नीतिगत निरंतरता और स्थिरता पूर्वपेक्षाएँ तो हैं ही, लेकिन ये अपने आप में वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित नहीं करतीं, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होती है। व्यवसायों और लोगों के लिए आत्मविश्वास के साथ व्यय और निवेश संबंधी निर्णय लेने हेतु वित्तीय स्थिरता आवश्यक है। भारत

¹ नए औद्योगिक लाइसेंस चाहने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में अब स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है, और जैसा कि केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की गई थी, इसे आगे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा। बाशर्ते पूरा प्रामियम भारत में ही निवेश किया जाए।

का वित्तीय क्षेत्र मज़बूत और सक्रिय है, जो विभिन्न आर्थिक कारकों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करता है।

वित्तीय क्षेत्र: बैंकिंग क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था की बड़ी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है, ने स्वस्थ तुलन-पत्र के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)² की सुदृढ़ता मज़बूत लाभप्रदता, कम अनर्जक आस्तियां और पर्याप्त पूँजी और चलनिधि बफर द्वारा समर्थित है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र की स्थिति भी मज़बूत है। बैंक ऋण वृद्धि, हालांकि हाल के महीनों में कम हुई है, पिछले 10 वर्षों में औसतन 10.5 प्रतिशत की तुलना में दोहरे अंकों (लगभग 12 प्रतिशत) में बनी हुई है। हम दक्षता और स्थिरता के साथ विनियमन को संतुलित करने पर जोर देते हुए बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों की क्षमता, प्रतिक्रियाशीलता और लचीलापन को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीडीपी के संदर्भ में निजी ऋण की मात्रा कम है। अतः निवेश के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हुए, बैंकिंग क्षेत्र समाज और उद्योग की निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।

पूँजी बाजार: भारतीय पूँजी बाजार - इकिवटी और ऋण - दोनों ही लगातार विकसित हो रहे हैं, जिससे कारोबार को बाजार-आधारित वित्तपोषण के अवसर मिल रहे हैं। भारत के पूँजी बाजारों में खुदरा और संस्थागत निवेशकों की सर्वोत्कृष्ट भागीदारी देखी गई है, जिससे बचत उत्पादक निवेशों में बदल रही है। आज, लगभग 106 मिलियन विशिष्ट डीमेट खाते और 54 मिलियन से अधिक विशिष्ट म्यूचुअल फंड खाते हैं। शेयर बाजार ने पिछले बीस वर्षों में औसतन 11 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की दर से प्रतिलाभ दिया है। 500 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों, जिनमें से प्रत्येक का बाजार पूँजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, के साथ, पूँजी बाजार भारत की विकास गाथा में भागीदारी के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। भारतीय वित्तीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए निर्बाध प्रवेश और निकासी प्रदान करते हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाता है।

² अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) दिसंबर 2024 के अंत में 12 साल के निचले स्तर अर्थात् 2.42 प्रतिशत पर आ गई और उनका सीआरएआर (सीआरएआर) 16.5 प्रतिशत पर रहा।

बाह्य क्षेत्र: भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में दबावों, जैसा कि पिछले कुछ महीनों में देखा गया, का सामना करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ता और चलनिधि मौजूद है। भारत का चालू खाता घाटा (अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत) मज़बूत सेवा निर्यात³ और निजी विप्रेषणों के समर्थन से, प्रबंधनीय सीमा के भीतर बना हुआ है। हाल के उत्तर-चढ़ाव भरे दौर में भी, भारतीय रूपया (आईएनआर) व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा है और अपने समकक्षों की तुलना में उसने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और हमारे विदेशी मुद्रा बाजार की सुदृढ़ता को दर्शाता है।

भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह अप्रैल-फरवरी 2024-25 में बढ़कर 75.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 65.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इससे विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर विश्वास परिलक्षित होता है। हालांकि, इस अवधि के दौरान अधिक प्रत्यावर्तन और बाह्य निवेश के कारण निवल एफडीआई प्रवाह में कमी आई, जो एक परिपक्व बाजार का संकेत है जिसमें विदेशी निवेशक आसानी से प्रवेश और निकासी कर सकते हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मज़बूत बना हुआ है। 18 अप्रैल 2025 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 686.1 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जो 11 महीनों के आयात और दिसंबर 2024 के अंत तक बकाया 96 प्रतिशत बाहरी ऋण के लिए पर्याप्त है।

मूल्य स्थिरता: टिकाऊ विकास और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में मूल्य स्थिरता की भूमिका सर्वोपरि है। भारत में मौद्रिक नीति ने राजकोषीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करते हुए एक स्थिरकारी भूमिका निभाई है। भारत ने 2016 में एक लचीले मुद्रास्फीति

³ वैधिक आर्थिक व्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद, सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक निर्यात के बल पर, भारत के सेवा निर्यात में 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वैधिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पिछले कुछ वर्षों में सेवा निर्यात के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरे हैं, जिनका भारत के सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय योगदान है। 1,800 से अधिक जीसीसी के साथ, इस क्षेत्र के 2024 के 64.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2030 तक 110 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

लक्ष्यीकरण ढाँचे को अपनाया, जिससे नीतिगत पूर्वानुमानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है: मुद्रास्फीति के स्तर और अस्थिरता में उल्लेखनीय कमी आई है, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ बेहतर ढंग से स्थिर हुई हैं, और मौद्रिक नीति के संचरण में सुधार हुआ है। सौम्य मुद्रास्फीति की संभावना और मध्यम संवृद्धि को देखते हुए, उदार मौद्रिक नीति रुख अपनाया गया है। हमने फरवरी 2025 से इस वर्ष नीतिगत ब्याज दरों में संचयी रूप से 50 आधार अंकों की कमी की है।

राजकोषीय विवेकशीलता और दक्षता

सरकार की राजकोषीय नीतियाँ आर्थिक विकास को उत्प्रेरित और उसे टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि बचत राशियों और सार्वजनिक निधियों का उत्पादक क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। भारत तीव्र और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय विवेक को अपनाए हुए है। महामारी के प्रति उसका दृष्टिकोण इसका एक उदाहरण है। भारत ने महामारी के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। अधिकांश देशों की तरह, प्रोत्साहन पैकेजों को पहले से लागू (फ्रंट लोडिंग) करने के बजाय, भारत ने समाज के कमज़ोर वर्गों और छोटी फर्मों की सहायता के लिए एक लचीला और चुस्त दृष्टिकोण अपनाया। इससे एक सुदृढ़ सुधार संभव हुआ क्योंकि इसके बाद पूंजीगत व्यय में वृद्धि और विनिर्माण को ठोस प्रोत्साहन दिया गया। महामारी से प्रेरित प्रोत्साहन के बाद सरकार अब राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध है, और व्यय की गुणवत्ता, यानी विकास को बढ़ावा देने वाले व्यय से समझौता किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात 2020-21 के 9.2 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 4.8 प्रतिशत हो गया है और बजट में इसे 2025-26 में और कम करके इसे 4.4 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। यह कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते क्रूण स्तरों के बिल्कुल विपरीत है। भारत का लोक क्रूण - जीडीपी अनुपात 81.3% (2024 में) है जो उचित है⁴, जबकि जर्मनी के अलावा दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं का लोक क्रूण भारत से अधिक है। भारत में राजकोषीय समेकन में वृद्धि ने निजी क्षेत्र के लिए निवेश हेतु संसाधन जुटाने की गुंजाइश बढ़ा दी है।

⁴ अनुमान है कि 2030 में यह घटकर 75.8 प्रतिशत हो जाएगी (आईएफ वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2025)।

इसके अलावा, सरकारी खर्च बेहतर तरीके से लक्षित है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2019-20 के 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 3.1 प्रतिशत हो गया है। राज्यों को पूंजीगत अनुदान सहायता सहित, यह 2025-26 में बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गया है⁵। इस वर्ष केंद्र सरकार की उधारी को प्रभावी पूंजीगत व्यय से कम रखने का बजट बनाया गया है, जो उत्पादक उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग को दर्शाता है जिसका उच्च गुणक प्रभाव होता है। सरकारी व्यय के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, जिससे अनुमान है कि लगभग 40 बिलियन अमरीकी डॉलर (मार्च 2023 तक) की बचत हुई है।⁶ 'आधार' को आधार बनाकर सार्वजनिक वितरण योजना जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के डिजिटलीकरण से भी भारी बचत हुई है। राज्य सरकार को समय पर धनराशि उपलब्ध कराए जाने से केंद्र सरकार को अपने नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिली है।

बुनियादी ढाँचे पर जोर

आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाँचा महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने भौतिक बुनियादी ढाँचे में भारी निवेश किया है। वह राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को भी प्रोत्साहित कर रही है, विशेष रूप से शहरी विकास, बिजली और पर्यटन के क्षेत्र में। राजमार्गों से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेलवे⁷ तक, भारत आने वाले दशकों तक टिकाऊ और समावेशी विकास का आधार तैयार कर रहा है। इससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है, बल्कि गुणक प्रभाव भी पैदा हो रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मांग

⁵ 2025-26 में 4.3 प्रतिशत (बजट अनुमान)।

⁶ <https://dbtibharat.gov.in/static-page-content/spagecont?id=18>

⁷ नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी), नेशनल मोनीटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) और पीएम गति शक्ति जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ अवसंरचना क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 60 प्रतिशत बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गया। पीएम गति शक्ति निर्बाध लॉजिस्टिक्स के लिए 6.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाओं को सुव्यवस्थित कर रही है। रेलवे ने 136 वंदे भारत ट्रेनें शुरू की हैं और 'अमृत भारत' स्टेशन योजना के तहत उन्नयन के लिए 1,337 स्टेशनों की पहचान की है। 20 से अधिक शहरों में मेट्रो नेटवर्क 248 किमी से बढ़कर 1,011 किमी हो गया है, और परिचालन हवाई अड्डे 74 से बढ़कर 159 हो गए हैं। भारत के विमानन क्षेत्र में हवाई संपर्क में सुधार के उद्देश्य से 'उड़े देश' का आप नागरिक (यूडीएन) के तहत 545 मार्गों के संचालन के साथ महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। पिछले एक दशक में 158 चालू हवाई अड्डों और 84 हवाई अड्डों के निर्माण के साथ, भारत का विमानन नेटवर्क तेज़ी से विकसित हो रहा है।

बढ़ रही है। इससे व्यवसायों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत में भी काफी कमी आ रही है और उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो रहा है।

विनिर्माण पर नए सिरे से ध्यान

विनिर्माण, समावेशी विकास और रोजगार की कुंजी है। हम 'आत्मनिर्भर भारत' पर केंद्रित हैं। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसे नीतिगत उपायों के सहयोग से, भारत का विनिर्माण क्षेत्र गति पकड़ रहा है और निवेश के लिए एक सशक्त क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। पीएलआई 14 विविध क्षेत्रों को लक्षित करता है।⁸ इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। 2018-19 से 2023-24 तक मोबाइल फोन निर्यात में लगभग 10 गुना⁹ वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, इसी अवधि में सौर सेल और मॉड्यूल के निर्यात में 20 गुना¹⁰ वृद्धि हुई है।

सक्रिय सरकारी नीतियाँ अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश के लिए अनोखे अवसर भी प्रस्तुत करती हैं। भारत स्थानीय सोसिंग और विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में अपनी स्थिति बना रहा है। यह एक वैश्विक एसएएस नवाचार केंद्र भी बन रहा है, विशेष रूप से जनरेटिव एआई के क्षेत्र में।

जनसांख्यिकीय लाभांश

28 वर्ष¹¹ की औसत आयु वाली सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक, भारत जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए तैयार है। इस क्षमता का पूरा दोहन करने के लिए, सरकार ने कौशल, उद्यमिता और प्रशिक्षिता के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इससे उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत

⁸ मोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और उसके घटक, सौर पीरी, इलेक्ट्रिक वाहन, और उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी।

⁹ 2018-19 के 1.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2023-24 में 15.6 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2024-25 में 18.3 बिलियन अमरीकी डॉलर (अप्रैल 2024 - जनवरी 2025)।

¹⁰ 2018-19 में 0.1 बिलियन अमरीकी डॉलर से 2023-24 में 2 बिलियन अमरीकी डॉलर (अप्रैल-जनवरी 2024-25 की अवधि के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर)।

¹¹ भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जिसकी औसत आयु मात्र 28 वर्ष है, जो अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

में श्रम बाजार की स्थितियाँ सकारात्मक रुझान¹² दिखा रही हैं, खासकर कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के साथ। श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पिछले वर्ष के 57.9% और 2017-18 के 49.8% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई है।

नवाचार

विशाल मानव संसाधनों का और अधिक लाभ उठाने के लिए, हमें मूल्य शृंखला में और आगे बढ़ना होगा। यह जानकर उत्साह मिलता है कि भारत तेज़ी से नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वालों का देश बनता जा रहा है। जब मैंने कॉलेज छोड़ा था, तब किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करना मेरा पसंदीदा विकल्प था। किसी ने भी अपना उद्यम शुरू करने की चुनौती स्वीकार नहीं की। हालाँकि, हाल के वर्षों में, बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और प्रबंधन स्नातक उद्यमिता और स्टार्ट-अप की ओर रुख कर रहे हैं। इस पीढ़ी द्वारा अपनाई जा रही उद्यमिता संस्कृति के परिणामस्वरूप, हमारे पास लगभग 1,50,000 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप हैं। हमारे पास एक सक्रिय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी समर्थन प्राप्त है। हमारे यहाँ तीसरी सबसे बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक में, भारत 2015 के 81वें स्थान से 2024 में 39वें स्थान पर पहुँच गया है। यह निम्न-मध्यम आय वाले देशों में प्रथम स्थान पर है।

व्यापार सुगमता और सुधारों पर निरंतर ध्यान

यह विकास मजबूत आर्थिक सुधारों द्वारा संचालित है, जिन्होंने दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि की नींव को मजबूत किया है। इन सुधारों में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (एफआईटी), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण, कॉर्पोरेट कर का युक्तिकरण और उसे कम किया जाना शामिल हैं। भारत

¹² बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं के लिए एलएफपीआर इसी अवधि के 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि औपचारिक रोजगार और भी बढ़ा है तथा 2024-25 की तीसरी तिमाही में शुद्ध पेरोल वृद्धि 4.2 प्रतिशत हुई है।

सरकार ने लगभग 1,500 अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। 180 प्रावधानों को गैर-अपराधी कोटि में परिवर्तित किया गया है और अन्य कुछ मामलों में भी इसे लागू करने की योजना है। इन सुधारों और अनुकूल नीतिगत परिवेश ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता¹³, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है।

सरकार विनियामक बोझ को और कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि इस वर्ष की शुरुआत में सभी गैर-वित्तीय क्षेत्रों में विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की बजट घोषणा से स्पष्ट है। उन्होंने विकास के तत्वों के रूप में सुधारों की भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय बजट का उद्देश्य छह क्षेत्रों - कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी सहकारी फेडरलिज़म की भावना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य निवेश अनुकूलता सूचकांक (इनवेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स) लॉन्च किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की एक व्यापक समीक्षा भी चल रही है ताकि इसे संक्षिप्त, सुबोध और आसान बनाया जा सके और विवादों और मुकदमों को कम किया जा सके। रिजर्व बैंक भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे विनियम स्थिरता और दक्षता के उद्देश्यों को संतुलित करें। इस प्रयोजन के लिए, विनियामक समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए) विनियमों की समीक्षा और उन्हें युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया का और विस्तार करेंगे और उसे व्यापकता और गति प्रदान करेंगे।

डिजिटलीकरण

भारत का डिजिटल परिवर्तन, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, व्यापार और जीवन को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक और आर्थिक विकास एवं नवाचार का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। अनुकूल सरकारी और विनियामक नीतियों, बढ़ती डिजिटल पहुँच और युवा एवं महत्वाकांक्षी जनसांख्यिकी ने इस सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है। सरकार ने जेएम ट्रिनिटी, यूपीआई, जीएसटीन, ओएनडीसी, डिजिलॉकर जैसे कई डिजिटल निर्माण खंडों में निवेश किया है। डिजिटलीकरण

दक्षता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, औपचारिकता को बढ़ावा और अर्थव्यवस्था में समावेशिता को बढ़ावा दे रहा है। सरकार के किसी भी क्षेत्र को लें, आप पाएंगे कि डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस ने टर्नअराउंड समय को बेहतर किया है, लागत कम की है और ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार किया है।

पिछले साल में यहाँ एक सत्र में इस बारे में बात करने आया था कि कैसे अन्य उपायों के अलावा, राजस्व विभाग में डिजिटलीकरण ने न केवल कर वृद्धि को बढ़ाया, बल्कि ग्राहक अनुभव और रिटर्न की प्रक्रिया में भी सुधार किया। पिछले चार वर्षों¹⁴ में व्यक्तिगत आयकर के लिए कर उछाल 2.1 रहा है। भारत में अब आयकर रिटर्न की प्रक्रिया में औसतन 10 दिन से भी कम समय लगता है: जो 2014 में 93 दिनों से कम है। इसके विपरीत, कुछ देशों में, कर धनवापसी प्राप्त करने में अभी भी महीनों लग जाते हैं।

रिजर्व बैंक भी डिजिटलीकरण और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और उसे समर्थन दे रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) इसका एक उदाहरण है। एक महीने में लगभग 18 बिलियन लेनदेन संसाधित करके, यह निर्बाध, सुरक्षित, रीयल-टाइम प्रणालियों में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। यूपीआई ने प्रदर्शित किया है कि कैसे सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के नवाचार को सशक्त बना सकती है। हमारा प्रोत्साहन और समर्थन भुगतान क्षेत्र से आगे बढ़कर विनियामक सैंडबॉक्स सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से व्यापक फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र तक फैला हुआ है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (यूएलआई), जो वर्तमान में प्रायोगिक चरण में है, में क्रण क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है। उम्मीद है कि यूएलआई क्रण और वित्त तक पहुँच को उसी तरह बदल देगा जैसे यूपीआई ने भुगतान क्षेत्र में किया।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनी हुई है जो मौद्रिक, वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता; नीतिगत स्थिरता

¹³ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत 67 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर है, जो बेहतर व्यावसायिक दक्षता को दर्शाता है।

¹⁴ पर्सनल इनकम टैक्स ब्यायांसी: 2021-22: 2.29; 2022-23: 1.42; 2023-24: 2.61; 2024-25: 1.94.

और निश्चितता; अनुकूल व्यावसायिक वातावरण; और मज़बूत समष्टिआर्थिक बुनियादी ढाँचों द्वारा समर्थित है। ऐसे समय में जब कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ आर्थिक चुनौतियों और बिगड़ते आर्थिक परिदृश्य का सामना कर रही हैं, भारत मज़बूत विकास और स्थिरता का प्रदर्शन करता आ रहा है, जिससे यह दीर्घकालिक मूल्य और अवसर चाहने वाले निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प बन गया है। इसके अलावा, हमारी मज़बूत घरेलू माँग¹⁵ और निर्यात पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी प्रभावों से बचाती है।

भारत एक पारदर्शी, नियम-आधारित और दूरदर्शी नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है जो दीर्घकालिक और उत्पादक निवेश के लिए एक आदर्श स्थान है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत केवल निवेश का एक गंतव्य ही नहीं है बल्कि यह समृद्धि में एक भागीदार भी है। साथ मिलकर, हमारे पास भविष्य को आकार देने का अवसर है – न केवल भारत के लिए, बल्कि एक बेहतर विश्व के लिए भी। मैं आपको इस यात्रा का हिस्सा बनने, सहयोग करने, नवाचार करने और भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

धन्यवाद।

¹⁵ घरेलू माँग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 90% का योगदान देती है, जबकि व्यापारिक निर्यात सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12% का योगदान देता है, जो हमारे कुछ समकक्षों की तुलना में बहुत कम है।